राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय

प्रमुख समाचार

मोदी की हत्या करने की अपील मामले में कांग्रेस नेता गिरफ्तार

दमोह। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को पन्ना पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पटेरिया के खिलाफ पन्ना के पवई में उनके कथित मोदी को मारो वाले बयान के सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। पटेरिया पर आईपीसी की धारा 451, 504, 505 (1)(बी), 505 (1)(सी), 506, 153-बी (1)(सी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस नेता को मंगलवार सुबह दमोह जिले के हट्टा स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया गया। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार को कांग्रेस नेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। रविवार को पवई रेस्ट हाउस में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित मंडलम सेक्टर अध्यक्षों की बैठक में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पटेरिया ने कथित तौर पर विवादित टिप्पणी की थी। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

बिहार में नीतीश सरकार को घेरने की तैयारी में भाजपा

पटना। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र मंगलवार से शुरू हो गया। भाजपा और उसके सहयोगी दल बिहार विधानसभा में महागठबंधन की सरकार को घेरने की तैयारी में हैं। भाजपा जबरदस्त तरीके से कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रहा है। इसके अलावा 10 लाख नौकरी के मुद्दे पर भी नीतीश कुमार के सरकार को घेरने की तैयारी में है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्य विधानसभा के बाहर कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर भाजपा विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बेरोजगारी को भी बड़ा मुद्दा बनाया गया। पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने साफ तौर पर कहा है कि महागठबंधन की सरकार ने बिहार की जनता से जो भी वादा किया है, उसे हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि महागठबंधन सरकार के आगमन के बाद राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरीके से चरमरा गई है।

पवार को जान से मारने की धमकी, युवक गिरफ्तार

मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार को जान से मारने की धमकी मिली है। उनके मुंबई स्थित आवास पर कोई व्यक्ति बार-बार फोन कर धमकी दे रहा था। इस मामले में जांच पड़ताल में जुटी पुलिस ने बिहार से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ये जानकारी पुलिस ने मंगलवार को दी है। जानकारी के मुताबिक गामदेवी थाने के एक अधिकारी एन सोनी को मुंबई पुलिस की टीम ने पटना से गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक को मुंबई ले जाया गया है। आरोपी युवक ने शरद पवार को अपशब्द भी कहे थे। वहीं शरद पवार ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है। पत्र में शिकायत की गई है कि कोई व्यक्ति फोन पर धमका देता है। धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ शरद पवार ने कार्रवाई करने की मांग की थी। वहीं शिकायत मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया है।

रामगढ़ विधायक समेत 13 दोषियों को 5-5 साल की सजा

रांची। रामगढ़ के इनलैंड पावर गोलकांड मामले में विधायक ममता देवी समेत 13 लोगों को पांच-पांच साल की सुनाई गयी है। हजारीबाग व्यवहार न्यायालय स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया। साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। मालूम हो कि कोर्ट ने गोलीकांड में विधायक ममता देवी समेत 13 लोगों को दोषी ठहराया था। इसी के तहत मंगलवार को कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। हजारीबाग व्यवहार न्यायालय के एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट के न्यायाधीश कुमार पवन ने मंगलवार शाम 3.40 बजे फैसला सुनाया है। न्यायाधीश ने रजरप्पा थाना कांड संख्या -79-2016 के तहत 13 आरोपियों को दोषी करार देते हुए अलग अलग धाराओं में सजा और जुर्माना निर्धारित किया है। विधायक ममता देवी का धारा 148 और 332 में दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है जबकि धारा 333 और 307 में पांच साल की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सभी सजा 13 आरोपियों को साथ-साथ चलेगी।

दिल्ली से चलती है मेघालय और असम की सरकार : ममता

शिलांग। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने शिलांग दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा सरकार पर तीखा हमला बोला। ममता ने कहा, मेघालय की सरकार असम और दिल्ली से चलती है। यहां के मुख्यमंत्री अपने लोगों की बात तक दिल्ली पहुंचा नहीं सकते। उनको वही काम करना पड़ता है, जो दिल्ली और पड़ोसी राज्य असम के हुक्मरान कहते हैं। वे स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। कार्यकर्ताओं को संबोधित करने से पहले वे मुकरो घटना में मारे गए लोगों के परिजनों से भी मिलीं और पांच-पांच लाख रुपये की सहायता राशि दी। इस दौरान उनके साथ तृणमूल कांग्रेस से महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी और मेघालय टीएमसी के अध्यक्ष मुकुल संगमा भी मौजूद थे। ममता ने कहा, चुनाव में आपको राजनीतिक पार्टियां पैसों का लालच देंगी। भाजपा या कोई अन्य दल अगर आपको पैसा दे तो ले लेना, क्योंकि ये आपके पैसे हैं, लेकिन वोट तृणमूल कांग्रेस को देना।

अमित शाह ने कांग्रेस की दुखती रग पर रखा हाथ

विवाद और चीन से आता फंड, भारत की 1 इंच भूमि पर भी कब्जा नहीं किया है

नईदिल्ली। भारत-चीन के बीच तनाव का दौर जारी है। दोनों देशों के बीच 1962 में एक बार जंग हो चुकी है। वहीं 1965 और 1975 में भी दोनों देशों के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं। इन तारीखों के बाद एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीनी घुसपैठ के बाद दोनों देशों के बीच तनाव के हालात हैं। ऐसे वक्त में जब सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर चीन से मुकाबला करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार भारत की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है। संसद का सत्र भी चल रहा है और विपक्ष की तरफ से चीनी घुसपैठ पर जबरदस्त हंगामा भी देखने को मिल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने चीन के मुद्दे को लेकर एक बयान दिया जिसको लेकर हंगामा मच गया है। उन्होंने अपने बयान में राजीव गांधी फाउंडेशन का जिक्र किया है।

गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में साफ किया कि भारत की 1 इंच भूमि पर भी कब्जा नहीं किया गया है। झड़प के वक्त भारतीय जवानों ने काफी वीरता दिखाई। कुछ ही समय में चीनी सैनिकों को वापस खदेड़ दिया। शाह ने आगे कहा कि चीन से 2005-2006 और 2006-2007 के बीच राजीव गांधी फाउंडेशन ने एक करोड़ 35 लाख रुपए लिए। फाउंडेशन का कहना है कि वह सामाजिक और रिसर्च वर्क के लिए पैसे देते थे, लेकिन इन पैसों का इस्तेमाल भारत-चीन संबंधों को मजबूत करने में किया गया। अगर कोई रिसर्च हुआ होता तो उसके रिपोर्ट दी गई होती।

बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए 21 जून 1991 को सोनिया गांधी ने इस फाउंडेशन की नींव रखी थी। ये फाउंडेशन एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रमोशन, शोषित (अंडरप्रिवलेज्ड) और दिव्यांगों के एम्पावरमेंट के लिए काम करता है। डोनेशन और इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले रिटर्न से इसका काम चलता है।

भारतीय जनता पार्टी ने इसे पहले भी आरोप लगाया था कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार और भारत में चीनी दूतावास ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले राजीव गांधी फाउंडेशन (आरजीएफ) को फंड किया है। सोनिया गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं और इसके बोर्ड में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन की सालाना रिपोर्ट के अनुसार साल 2005-06 में राजीव गांधी फाउंडेशन को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार और चीनी दूतावास से दो अलग-अलग दानकर्ताओं के रूप में डोनेशन प्राप्त हुआ था।

तवांग में हुई झड़प को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार से मांगा स्पष्टीकरण

नई दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में हुई भारत-चीन की झड़प को लेकर विपक्ष ने मंगलवार को केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सदन से वॉक आउट भी किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमें सदन के नेता और राज्यसभा के उपसभापति ने कहा कि हमें स्पष्टीकरण का एक मौका दिया जाएगा लेकिन उन्होंने नहीं दिया और हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे। यह देश के लिए अच्छा नहीं है।

राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, जब उन्होंने हमें स्पष्टीकरण नहीं दिया तो विपक्षी दलों के सभी नेताओं ने वॉकआउट करने का फैसला किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, हम अपने देश की एकता और अखंडता के लिए एक साथ खड़े हैं, हम अपने सैनिकों के साथ हैं। खड़गे ने कहा, उन्होंने (रक्षा मंत्री) अपना बयान पढ़ा और बाहर चले गए। वह किसी स्पष्टीकरण या चर्चा के लिए तैयार नहीं थे। इसका (राजीव गांधी फाउंडेशन एफसीआरए लाइसेंस रद्द करने का मुद्दा) कोई संबंध नहीं है। वहीं इस मुद्दे पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (एआईएमआईएम) पार्टी के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल किया। उन्होंने कहा, पीएम राजनीतिक नेतृत्व दिखाने में नाकाम रहे हैं। झड़प 9 दिसंबर को हुई थी और आप आज बयान दे रहे हैं। अगर मीडिया ने रिपोर्ट नहीं की होती, तो आप नहीं बोलते। सभी पक्षों को संघर्ष स्थल पर ले जाएं। एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा, पीएम चीन का नाम लेने से डर रहे हैं, उनकी सरकार चीन के बारे में बोलने से डर रही है। इससे पहले तवांग क्षेत्र में हुए भारतीय सेना और पीएलए के बीच झड़प को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय सैनिकों के साथ आमना-सामना के दौरान चीन द्वारा भारत की एक इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया गया है। भारतीय सैनिकों ने झड़प के दौरान अपार बहादुरी दिखाई और कुछ ही देर में चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया।

नाराजगी की अटकलों के बीच नीतीश का बड़ा बयान

2025 में तेजस्वी यादव ही महागठबंधन का नेतृत्व करेंगे

पटना। बिहार में महागठबंधन विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनके बाद उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही महागठबंधन का नेतृत्व करेंगे। 2025 का बिहार चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा।

नीतीश ने कहा कि भाजपा को हटाना ही उनका लक्ष्य है। मैं प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं, भाजपा को हटाने के लिए, आगे बढ़ना चाहता हूं। इतनी सी ही बात है। इसे ही गढ़ना होगा। इसलिए महागठबंधन के विधायकों को एकजुट होना होगा। दरअसल, कुढ़नी उपचुनाव में हार के बाद यह बात अटकलें लगाई जाने लगी थी कि राजद ने जदयू का साथ नहीं दिया और महागठबंधन में इस वक्त कुछ भी ठीक नहीं है।

महागठबंधन की बैठक पर राजद के ऋषि कुमार ने कहा कि हमने अपनी राजनीतिक रणनीति पर बैठक की थी। नीतीश कुमार ने कहा कि वह आने वाले समय में सीएम नहीं बनना चाहते हैं। दूसरे नंबर के नेता हैं- तेजस्वी यादव। अगर सीएम पद पर नहीं बने रहना चाहते हैं तो उनकी जगह दूसरे मैन इन कमांड लेंगे।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को एक बार फिर आरोप लगाया था कि 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने गठबंधन के बावजूद जद (यू) को हराने की साजिश रची थी। उन्होंने दोहराया कि भाजपा विरोधी दल 2024 के लोकसभा चुनावों में भारी बहुमत से जीत सकते हैं, अगर वे एक-दूसरे से हाथ मिलाने के लिए सहमत हों।

उन्होंने आरोप लगाया था कि पिछले विधानसभा चुनावों में उनके दल के असंतोषजनक प्रदर्शन का कारण भाजपा ही थी। पूर्व गठबंधन सहयोगी भाजपा का नाम लिए बिना नीतीश ने कहा था कि उन्हें (भाजपा) याद दिलाना चाहिए कि चाहे 2005 या 2010 के विधानसभा चुनाव हों, इससे पहले कभी भी हमारी पार्टी ने कम सीटें नहीं जीती थीं। 2020 में हमें नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने हमारे उम्मीदवारों को हराने की कोशिश की।

नीतीश ने यह भी कहा था कि वह एक और कार्यकाल के लिए सीएम बनने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन भाजपा के आग्रह पर पद संभालने को राजी हुए। उन्होंने कहा कि बिहार को केंद्र सरकार से कुछ नहीं मिला। वह (पीएम नरेंद्र मोदी) उस राज्य से ताल्लुक रखते हैं जो ब्रिटिश राज के समय से ही समृद्ध रहा है। गरीब राज्यों का विकास किए बिना देश प्रगति नहीं कर सकता।

उपचुनाव में महागठबंधन को लगा था झटका

इससे पहले बिहार की कुढ़नी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में महागठबंधन को बड़ा झटका लगा था। यहां भजापा प्रत्याशी को 76722 वोट मिले थे, इसके मुकाबले जदयू को 73073 वोट से संतोष करना पड़ा था। भाजपा ने केदार प्रसाद गुप्ता और महागठबंधन ने मनोज कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया था।

खेल

प्रमुख समाचार

फ्रांस-क्रोएशिया ने सेमीफाइनल में एकसाथ पहुंचकर रचा इतिहास

दोहा। फीफा विश्व कप के 92 साल के इतिहास में ऐसा संयोग सिर्फ एक बार बना है, जब पिछली बार की फाइनलिस्ट टीमों ने एक साथ विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया या टॉप चार टीमों में स्थान बनाया है। गत विजेता फ्रांस और उपविजेता क्रोएशिया दोनों इस बार सेमीफाइनल में पहुंचे हैं।

इससे पहले ऐसा 32 साल पहले हुआ था जब 1986 की विजेता अर्जेंटीना और उपविजेता पश्चिम जर्मनी ने 1990 के विश्व कप में एक साथ सेमीफाइनल में प्रवेश किया। यही नहीं उस दौरान इन दोनों टीमों ने फाइनल में भी जगह बनाई, जहां दिग्गज लोथार मथायस की कप्तानी में पश्चिम जर्मनी ने महान डिएगो माराडोना की अगुवाई वाली अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर न सिर्फ खिताब जीता बल्कि 1986 के फाइनल की हार का बदला भी ले लिया।

फ्रांस-क्रोएशिया के सामने 1990 की उपलब्धि दोहराने की चुनौती

यह किसी आश्चर्य से कम नहीं है कि फीफा विश्व कप के इतिहास में पिछली बार की फाइनलिस्ट टीमों के अगले विश्व कप में एक साथ सेमीफाइनल में पहुंचने का यह सिर्फ दूसरा मौका है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि फ्रांस और क्रोएशिया इस बार भी फाइनल में पहुंचने की उपलब्धि हासिल कर पाते हैं या नहीं।

पिछली बार 1990 में जब ऐसा हुआ तब अर्जेंटीना और पश्चिम जर्मनी ने फाइनल में प्रवेश किया। 1986 के फाइनल में माराडोना की अगुवाई में अर्जेंटीना ने पश्चिम जर्मनी को 3-2 से हराया था, लेकिन 1990 के फाइनल में पश्चिम जर्मनी ने अर्जेंटीना को आंद्रियास ब्रेहमे की गोल की बदौलत हराया।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/

प्रमुख समाचार

सेंसेक्स में 402 अंकों की उछाल, निफ्टी 18600 के पार

नई दिल्ली। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में हरियाली दिखी। मंगलवार को सेंसेक्स 402 अंकों की तेजी के साथ 62533 के स्तर पर बंद हुआ जबकि निफ्टी 110 अंकों की तेजी के साथ 18608 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। बाजार में पीएसयू बैंक, आईटी, बैंकिंग और ऑटो सेक्टर के शेयरों में बढ़त दिखी। इस दौरान बैंक निफ्टी 237 अंकों की बढ़त के साथ 43946 के स्तर पर बंद हुआ। मंगलवार के दिन बैंक निफ्टी 43983 पर पहुंचा जो इसमें नया ऑल टाइम हाई है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में 24 तेजी के साथ बंद हुए जब छह शेयरों में में कमजोरी दिखी। सोमवार के कारोबारी सेशन में बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजी के शेयरों में मजबूती दिखी जबकि नेस्ले इंडिया, टाटा स्टील, मारुति और टाइटन के शेयरों में कमजोरी दिखी।

एसबीआई ने एफडी पर बढ़ा दिया ब्याज

नई दिल्ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एफडी पर ब्याज दर में 65 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी की है। एसबीआई ने हाल में रेपो रेट में 35 बेसिस अंक की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद एसबीआई ने एफडी पर ब्याज दर बढ़ाया है। एसबीआई के वेबसाइट के मुताबिक बैंक ने एफडी पर ब्याज में 25 से लेकर 65 बेसिस पॉइंट्स तक की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी दो करोड़ रुपये तक के फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर की गई है। बढ़ा हुआ रेट 13 दिसंबर, 2022 से ही लागू हो गए हैं। इससे पहले बैंक ने 22 अक्टूबर को रिटेल टर्म डिपॉजिट्स पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की थी। बैंक ने 211 दिन से एक साल से कम अवधि के डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट 5.50 फीसदी से बढ़ाकर 5.75 फीसदी कर दिया है।

शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 24 % से बढ़कर हुआ 8 177 लाख करोड़

नई दिल्ली। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-नवंबर अवधि के दौरान सालाना आधार पर 24.26 फीसदी बढ़कर 8.77 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया। यह आंकड़ा 2022-23 के पूरे बजट अनुमान का 61.79 फीसदी है। चालू वित्त वर्ष के बजट में प्रत्यक्ष कर संग्रह 14.20 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है। यह 2021-22 के दौरान कुल 14.10 लाख करोड़ के कर संग्रह से अधिक है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 30 नवंबर, 2022 तक 8.77 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया। आंकड़ों के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष यानी 2022-23 के दौरान एक अप्रैल से 30 नवंबर के बीच करदाताओं को 2.15 लाख करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए गए। यह आंकड़ा 2021-22 की तुलना में 67 फीसदी अधिक है। कर संग्रह किसी भी देश की आर्थिक और कारोबारी गतिविधियों में बढ़ोतरी का संकेतक है।

यूनियन बैंक का कर्ज 0.05 फीसदी महंगा

नई दिल्ली। सरकारी क्षेत्र के यूनियन बैंक ने सभी अवधि के कर्ज की सीमांत लागत आधारित दर (एमसीएलआर) 0.05% बढ़ा दी है। नई दर 11 दिसंबर से लागू है, जो 10 जनवरी तक रहेगी। बैंक के मुताबिक, अब 6 माह के लिए एमसीएलआर 8.05%, एक व दो साल के लिए 8.45% और तीन साल के लिए 8.60% होगी। बैंक ने सोमवार को यह जानकारी दी। एअर इंडिया अमेरिकी एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग से 50 पतली बॉडी वाली 737 मैक्स जहाज खरीदने की योजना बना रही है। यह विमान वह एयर एक्सप्रेस के लिए खरीदेगी। यह सौदा उस रणनीति का हिस्सा है, जिसमें एअर इंडिया बड़े पैमाने पर बोइंग से खरीदी की योजना बना रही है। एअर इंडिया को टाटा समूह ने इसी साल जनवरी में खरीद लिया था।

पीसीआर के विचार को साकार करने का समय

तमाल बंद्योपाध्याय

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 6 जून, 2018 को ऐलान किया था कि 'मॉड्यूलर और चरणबद्ध तरीके' से पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री (पीसीआर) की स्थापना की जाएगी। साथ ही उसने वाईएम देवस्थली की अध्यक्षता में भारत के लिए पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री पर उच्चस्तरीय कार्यबल की रिपोर्ट भी जारी की थी। कार्यबल की स्थापना के पीछे 'क्रेडिट की मौजूदा उपलब्धता की सूचना की समीक्षा, मौजूदा सूचना उपयोगिताओं की पर्याप्तता और उन रिक्तताओं को चिह्नित करने' का उद्देश्य था, जिनकी पीसीआर से भरपाई की जा सके।

इससे पहले 4 अप्रैल, 2018 को जमा की गई इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि, 'सूचना विसंगति को दूर करने और कर्ज तक बेहतर पहुंच को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था में क्रेडिट संस्कृति को मजबूत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक पीसीआर स्थापित किया जाना चाहिए।'

क्या किसी को इस परियोजना की प्रगति के बारे में कुछ पता है? विभिन्न डेटाबेस से वित्तीय और गैर-वित्तीय जानकारी एकत्र करने के लिए एक केंद्रीकृत डेटाबेस ही पीसीआर कहलाता है। इसके पीछे विचार यही विचार था कि ऐसे सभी ब्योरे को दर्ज किया जाए, जिसकी नियामक, ऋण प्रदाता संस्थान, क्रेडिट ब्यूरो, रेटिंग एजेंसियों और यहां तक कि ऋण लेने वालों को जानने की आवश्यकता होती है।

सेंट्रल रिपॉजिटरी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स (सीआरआईएलसी) की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया शुरू हुई। जून 2014 में जब तक आरबीआई ने सीआरआईएलसी की स्थापना नहीं की थी, तब तक बैंकों के फंसे हुए कर्जों के आंकड़ों में असंगति दिखती थी। सीआरआईएलसी से

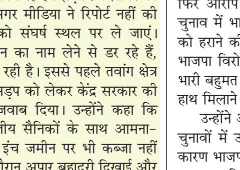

कई साल पहले 2008 में बैंकिंग नियामक ने क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाने का प्रयास किया, जहां बैंक बैड लोन्स (फंसे हुए कर्ज) का डेटा साझा कर सकते थे।

मगर यह कारगर नहीं रहा और इस प्रकार आरबीआई के पास किसी भी कर्ज लेने वाली की व्यापक क्रेडिट इन्फॉर्मेशन नहीं थी। सीआरआईएलसी की व्यवस्था के दौरान बैंकों ने पांच करोड़ रुपये और उससे अधिक के कर्जों के मामले में रियल टाइम डेटा की आपूर्ति शुरू कर दी थी। उसमें बैड अकाउंट्स के मामले में डेटा साप्ताहिक और गुड अकाउंट्स के मामले में मासिक रूप से उपलब्ध होता। केवल आरबीआई और बैंक ही उस डेटा को एक्सेस कर सकते थे, लेकिन ऋण लेने वालों और रेटिंग एजेंसियों तक उसकी पहुंच नहीं थी।

यह प्रत्येक बड़े कर्जदार (बारोअर) को लेकर बैंकों के एक्सपोजर की व्यापक तस्वीर दिखाने के साथ यह भी दर्शाता कि कहीं उसी कर्जदार को अलग-अलग बैंकों ने भिन्न-भिन्न रूप में वर्गीकृत तो नहीं किया। वहीं सीआरआईएलसी के अस्तित्व में आने से साल भर पहले आरबीआई ने अपने पर्यवेक्षण प्रतिरूप को केमल्स-सीएएमईएलएस (पूंजी पर्याप्तता, परिसंपत्ति गुणवत्ता, प्रबंधन, आय, तरलता और तंत्र एवं नियंत्रण) से बदलकर जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) कर दिया। आरबीएस और सीआरआईएलसी की जुगलबंदी ने नियामक को बैंकिंग परिदृश्य के विभिन्न पहलुओं से भलीभांति अवगत कराया और इससे सिस्टम-वाइड ऑडिट की राह खुली। इस प्रकार भारतीय बैंकिंग की सेहत के अपनी तरह के पहले परिमापक-परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) की संकल्पना आकार ले पाई।

जहां तक पीसीआर की बात है तो यह-खुदरा, कॉरपोरेट और एमएसएमई जैसी सभी श्रेणियों से जुड़ी सूचना को समाहित करने वाली एकल खिड़की है, जिसमें कर्ज के आकार की कोई न्यूनतम सीमा भी नहीं। यहां तक कि कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ऐंड सिक्योरिटी इंट्रेस्ट ऑफ इंडिया और वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क्स जैसे बाहरी स्रोतों से मिले डेटा को भी इस फ्रेमवर्क में जोड़ा जा सकता है। दरअसल, यह किसी भी कर्जदाता की वित्तीय सेहत का कहीं व्यापक ब्योरा प्रदान करता है, जिसमें बैंकिंग तंत्र से इतर कॉरपोरेट फाइलिंग और टैक्स एवं यूटिलिटी भुगतान जैसे पहलुओं का भी जुड़ाव शामिल है।